मूल्य 1 रु.
वर्षः 10 - अंक : 84, मुंबई, शुक्रवार, 29 मई, 2020 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादकः दिलशाद एस. खान
दैनिक
मुंबई हलचल
भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त ®
अब हर सच होगा उजागर

महाराष्ट्रः 'अस्थिरता' की अफवाह के बीच विधान परिषद में... मजबूत होता गठबंधन

बीजेपी परेशान

मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के अस्थिर होने की खबरों के बीच एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी के सदस्य दलों में एकजुटता के दृश्य दिखने वाले हैं। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। प्रदेश के विधान परिषद की 12 सीटों के लिए गठबंधन सरकार ने 12 लोगों के नाम की सिफारिश राज्यपाल से की है। एमएलसी मनोनयन के लिए भेजे गए उम्मीदवारों के नाम में तीनों दलों के 4-4 उम्मीदवार हैं। (शेष पृष्ठ 3 पर)

महाराष्ट्र विधानपरिषद की 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्यपाल से की है। इनमें सत्ताधारी तीनों दलों के 4-4 उम्मीदवार शामिल हैं। विधानपरिषद में गठबंधन सरकार की ताकत बढ़ने से विपक्षी दल बीजेपी परेशान है।

बीजेपी नेतृत्व पर संकटः राउत

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि गठबंधन सरकार बहुत आराम से काम कर रही है। वास्तविक संकट तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर है। वे लोग चाहे जितना छिपाने की कोशिश कर लें, उनकी आंतरिक कलह खुलकर सामने आ ही जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन राउत ने भी संजय राउत की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि फडणवीस थक गए हैं और सत्ता को लेकर अपने लालच के कारण अधीर भी हो गए हैं। इसके अलावा बीजेपी की आंतरिक कलह से निपटने में भी असमर्थ रहे हैं। राउत ने कहा कि फडणवीस को अब थोड़ा यथार्थवादी होना चाहिए और कोविड-19 के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई में उसका साथ देना चाहिए।

कोरोनाः धारावी से आखिर मिलने लगी गुड न्यूज, मेहनत लाई रंग

(समाचार पृष्ठ 3 पर)

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

राज्य सरकारें देंगी प्रवासी मजदूरों का किराया और खाना

संवाददाता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग-अलग शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों के बारे में गुरुवार को बड़ा फैसला दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन मजदूरों की बदहाली पर केंद्र से कुछ तीखे सवाल भी पूछे। उसने केंद्र को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर पहुंचाने के लिए प्रवासी मजदूरों से कोई किराया नहीं वसूला जाए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूछा कि इन प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचने के लिए कितना इंतजार करना होगा, उनका किराया कौन देगा, खाने-पीने और रहने के प्रबंध की जिम्मेदारी कौन करेगा। (शेष पृष्ठ 3 पर)

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

संपादकीय

चिंता बढ़ाते आंकड़े

यह एक ऐसी गिनती है, जिसको गिनने की बदकिस्मती से हम बच नहीं सकते और इसके आंकडे.रोज हमारी चिंताओं में इजाफा कर जाते हैं। कल देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या डेढ़ लाख का आंकड़ा पार कर गई और पिछले छह दिनों से लगातार छह हजार से ज्यादा नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। हम इस महामारी के शिकार शीर्ष दस देशों में आ गए हैं। हालांकि, आईसीएमआर अब भी वायरस के सामुदायिक प्रसार की आशंका को नकार रहा है, तो यकीनन यह कुछ सुकून की बात है। पर जिस तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और अब बिहार में इसकी तीव्रता दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाने में ये प्रदेश चूक गए। ऐसा मानने का आधार है। विदेश को छोड़िए, देश में ही केरल ने यह बताया है कि किसी महामारी से निपटने के लिए कैसी सूझबूझ, तैयारी और प्रशासनिक कौशल की जरूरत पड़ती है। हमारे यहां कोरोना का पहला मामला केरल में ही 30 जनवरी को सामने आया था और आज वह संतोष जता सकता है कि पिछले चार महीने में उसके यहां संक्रमितों की संख्या हजार से भी नीचे रही, बल्कि इनमें भी आधे से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उसकी यह उपलब्धि तब है, जब उसके यहां जनसंख्या घनत्व कई राज्यों के मुकाबले अधिक है और विदेश में रहने वाले नागरिक भी बड़ी संख्या में वहां लौटकर आए हैं। केरल की ही तरह, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी लॉकडाउन की अवधि का अपेक्षाकृत बेहतर उपयोग किया है। बल्कि आज हम जिस मुकाम पर हैं, उसमें अकेले महाराष्ट्र का एक तिहाई योगदान है। शुरुआत में राज्य सरकार वहां हालात को नियंत्रित करती हुई दिखी भी थी, मगर उसके बाद कुछ जैसे उससे छूटता-सा गया। कभी अस्पतालों से बदइंतजामी झांकती मिली, तो कभी फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती भीड़ स्टेशनों पर उमड़ती दिखी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से आईं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो एक वक्त इतने आश्वस्त थे कि चंद रोज के भीतर वह अपने यहां कोरोना पर पूर्ण नियंत्रण का एलान करने जा रहे थे। आज उनका प्रांत संक्रमण के मामले में नंबर दो पायदान पर है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब राज्य लॉकडाउन में रियायत देने को बाध्य हैं, क्योंकि उन्हें राजस्व भी चाहिए, और उन पर कारोबार जगत का भी दबाव है। कोविड-19 से जंग की एक विश्व-व्यापी सच्चाई यही है कि जिन भी देशों-प्रदेशों ने एक स्पष्ट नीति बनाई, और उस पर सख्ती से अमल किया, वे आज बेहतर स्थिति में हैं। इसके उलट, जहां कहीं भी उपायों के स्तर पर ऊहापोह की स्थिति रही, वहां के नागरिक समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमने बहुत पहले देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू करके एक अच्छी रणनीति अपनाई थी और इसका फायदा भी हुआ है, मगर हम इससे अपेक्षित लाभ नहीं उठा सके।

कोरोना काल में शिक्षा को लेकर सामने कई चुनौतियां

वर्तमान वैश्विक महामारी के प्रकोप ने जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है। इस दौर में शिक्षा के क्षेत्र में एक तरफ जहां विविध प्रकार की चुनौतियां खड़ी हुई हैं, वहीं उन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न प्रयोग भी हो रहे हैं। प्राथमिक व माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। शहर तो शहर, गांवों में भी ऑनलाइन अध्ययन-अध्यापन की यह व्यवस्था कमोबेश देखने-सुनने में आने लगी है। वीडियो कांफ्रेंसिंग से लेकर संचार व संपर्क के अन्य माध्यमों तक से अध्यापक आज घर बैठे छात्रों को पढ़ाने में लगे हैं।

इन शैक्षिक नवाचारों के बीच ही पिछले दिनों देश के प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसका सार यह था कि वर्तमान महामारी द्वारा पैदा परिस्थितियों के कारण स्नातक और परास्नातक कर रहे अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय ओपन बुक मोड में परीक्षा करवाने जा रहा है। इस तरीके से परीक्षा में यह होगा कि छात्रों को तय प्रारूप के अंतर्गत प्रश्न भेजे जाएंगे जिन्हें उनको एक निर्धारित समय के भीतर लिखकर ऑनलाइन भेजना होगा। इस विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन एग्जामिनेशन द्वारा दी गई जारी जानकारी के मुताबिक प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया जाएगा, कुल छह प्रश्न होंगे जिसमें से विद्यार्थियों को चार प्रश्न हल करने होंगे और एक घंटे के अंदर उसे वापस भेज देना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की इस घोषणा के बाद से ही डीयू के छात्र संघ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एकसाथ इसके विरोध में खड़े हैं। इस घोषणा के बाद ट्विटर पर डीयू अगेन्स्ट ऑनलाइन एग्जाम हैश टैग के साथ हजारों की तादाद में विद्यार्थियों ने ट्वीट कर इस निर्णय के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय जिस प्रकार की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए छात्रों के पास कंप्यूटर-लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ-साथ अच्छे इंटरनेट की उपलब्धता भी आवश्यक है। ऐसे में जिन छात्रों के पास ये तकनीकी संसाधन नहीं होंगे, वे कैसे इस परीक्षा में भाग ले पाएंगे? आखिर वह कौन-सा तंत्र है जिसने यह सुनिश्चित कर लिया कि छात्रों के पास कंप्यूटर-लैपटॉप जैसे संसाधन तथा बढ़िया इंटरनेट भी उपलब्ध होंगे? क्या डीयू प्रशासन की तरफ से कभी अपने सभी छात्रों को यह संसाधन उपलब्ध कराए गए थे? जवाब है, नहीं।

तो जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो इस संकट काल में अचानक विश्वविद्यालय प्रशासन किस आधार पर छात्रों से ऑनलाइन परीक्षा देने की अपेक्षा कर रहा है? इतना ही नहीं, ऑनलाइन परीक्षा का जो प्रारूप विश्वविद्यालय ने तय किया है, उसमें न्याय की भावना भी कम ही दिखती है। क्या यह संभव नहीं कि कोई कम पढ़ा छात्र इस ओपन बुक परीक्षा में किताब की सहायता से बेहतर कर जाए, जबकि कोई खूब पढ़ा छात्र तकनीकी संसाधनों के अभाव में परीक्षा देने से ही वंचित रह जाए। जाहिर है, ऑनलाइन परीक्षा का यह प्रारूप फिलहाल किसी भी ढंग से उचित व व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता।

कोरोना त्रासदी: आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर कई तरह की समस्याएं श्रमिकों के समक्ष आएंगी

देश के उन अधिकांश राज्यों या महानगरों से प्रवासी श्रमिक अपने गांव-घर लौट रहे हैं, जहां दशकों से वे किसी न किसी छोटे-मोटे उद्योग धंधे से जुड़े हुए थे या फिर दिहाड़ी मजदूर के रूप में या रेहड़ी-पटरी पर कोई काम करके अपना गुजारा चला रहे थे। कई तो ऐसे भी हैं जो कहीं मैकेनिक, निर्माण मजदूर, कामगार आदि के रूप में कार्यरत थे।

इसे रोजगार छूट जाने के बाद नगरों या महानगरों में गुजारा होना मुश्किल कहें या फिर महामारी के दौर में अपनों के साथ रहने की इच्छा या अपने पैतृक आंगन में लौट जाने का भावनात्मक जुड़ाव, अब तक इन कारणों से लाखों की संख्या में मजदूर देश के दूर-दराज के गांवों में पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह विचारणीय है कि तपती सड़क पर पैदल चलकर या फिर ट्रक, बस, ट्रेन आदि के जरिये गांव पहुंचने के बाद भी मजदूरों की समस्याएं खत्म नहीं होने वाली हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से सेहत सहेजने और सरकार की मदद के मोर्चे पर जो परेशानियां उनके हिस्से आई हैं, उससे कहीं ज्यादा परेशानियां श्रमिकों को समाज और परिवार के मोर्चे पर भी झेलनी हैं। गांव लौट रहे मजदूरों की टोलियों से गांवों में बढ़ता जन-दबाव वहां की

पूरी सामाजिक-पारिवारिक रूपरेखा को बदलने वाला साबित होगा। इस महामारी के दौर में बरसों बाद घर लौट रहे कई मजदूरों को वहां भी रोजगार के मोर्चे पर तो मुश्किलें झेलनी ही हैं, अपनों-परायों के व्यवहार के पहलू पर भी उपेक्षा का रवैया उनके हिस्से आए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। दरअसल ग्रामीण समाज भी अचानक इस बढ़ते जन-दबाव को झेलने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों का घर लौटना गांवों में कई चुनौतियों को भी जन्म देगा। चिंतनीय यह भी है कि महामारी के बीच हमारे देश में गांवों-कस्बों में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। इतना ही नहीं, अचानक अपनों के बीच लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक संबंधों के मोर्चे पर भी बहुत कुछ अजब-अनपेक्षित देखने को मिल सकता है। कई मजदूर परिवार सहित बरसों बाद घर लौट रहे हैं। इस दौरान कभी काम छूट जाने की मजबूरी के चलते तो कभी आने-जाने का खर्च न कर पाने की स्थिति में जाने कितने ही सुख-दुख के मौकों पर वे अपनों के पास नहीं पहुंच पाए होंगे। ऐसे लाखों परिवार बरसों से अपने घर आंगन से दूर महानगरों में गुजर-बसर कर रहे थे। अब घर लौट आने की वजह बन रही कोरोना त्रसदी के समय सामाजिक-पारिवारिक पहलू पर उनके प्रति गांव या घर में कितनी सहज स्वीकार्यता होगी? यह एक व्यावहारिक और विचारणीय पहलू है। यह कटु सच है कि उनके अपनों के पास पीड़ा के इस दौर में भी उलाहने देने और दूरियां बनाने के कारणों की एक लंबी फेहरिस्त होगी। यों भी इस संक्रामक बीमारी के डर ने दूरियां बनाने का बहाना दे ही दिया है। इन दिनों ऐसी कई खबरें भी आई हैं जो गांव लौटे मजदूरों के प्रति अपनों-परायों के उपेक्षा भरे व्यवहार की बानगी बनी हैं। कई मजदूरों ने कहा कि उनके घर वाले उनके साथ अजनबियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। गांव वाले उनसे दूरी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, संक्रमण फैलने के डर से करीबी लोग भी उन्हें गांव नहीं आने की सलाह दे रहे हैं।

कोरोना: धारावी से आखिर मिलने लगी गुड न्यूज, मेहनत लाई रंग

मुंबई के रेड जोन से बाहर आने में धारावी की होगी भूमिका

संवाददाता

मुंबई। मुंबई में बढ़ते कोरोना मामलों में बहुत हद तक वजह स्लम एरिया धारावी को माना जा रहा है। जहां कोरोना के कुल 1,541 मामले हैं। घनी आबादी के कारण यहां कई चुनौतियां भी सामने आईं मसलन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साफ-सफाई। इसके धारावी के साथ आस-पास के इलाके भी कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए। हालांकि, राहत की बात यह है कि अब धारावी में कोरोना मामलों में थोड़ा सुधार हुआ है। बुधवार को यहां एक दिन में सबसे कम 18 संक्रमित सामने आए। वहीं कोरोना के दोगुनी होने की रफ्तार और औसत ग्रोथ रेट भी कम हुआ है।

धारावी में कुल 1,541 कोरोना केस हैं जिनमें से 453 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। यहां कोरोना के दोगुनी होने की दर अब 3 दिन से 19 दिन हो गई है जबकि पूरे मुंबई में यह दर 11 दिन है। अगर ऐसा ही रहा कि धारावी में भी डी वार्ड (वर्ली, लोवर परेल) की तरह सुधार देखने को मिल सकता है। जहां 21 मई तक 812 केस थे जिनमें से 410 ठीक हो चुकी है। धारावी में अब तक 59 की मौत हो चुकी है। उत्तरी मुंबई के जी वॉर्ड में कुल 2,077 कोरोना मामले हैं। इसी वार्ड में दादर, महीम और धारावी जैसे इलाके हैं। जी वार्ड में कोरोना की औसत रेट घटकर 5.1 फीसदी हो गई है जिसका आकलन पिछले सात दिनों में कोरोना के मामले को देखते हुए किया गया है। जबकि मुंबई में कोरोना की औसत ग्रोथ रेट 6 फीसदी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल दो हफ्ते पहले दिल्ली की एक्सपर्ट टीम के साथ धारावी में थे। इस पर कोई शक नहीं कि लॉकडाउन खत्म होने के लिए मुंबई को रेड जोन से बाहर निकलना होगा और इसके लिए धारावी में कोरोना मामलों की संख्या को स्थिर करना होगा।

धारावी में कैसे रंग ला रही है मेहनत

धारावी में पहला केस 1 अप्रैल को सामने आया था। 15 अप्रैल तक यहां 100 केस हो चुके थे। 27 अप्रैल से 15 मई तक जी नॉर्थ वार्ड में 95 केस सामने आए, इनमें से अधिकतर स्लम एरिया से आए। अब यह औसत दर घटकर 25 हो गई है। वार्ड के अपर निगम आयुक्त किरण दिघावकर ने बताया, अग्रेसिव टेस्टिंग यानी अधिक से अधिक जांच इसके पीछे बड़ा फैक्टर है। बीएमसी के साथ प्राइवेट डॉक्टर और अस्पताल भी आगे आए और बड़ी मदद की। हमने स्लम इलाकों में 4.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की। 24 प्राइवेट डॉक्टरों ने डोर-टु-डोर स्क्रीनिंग की। उन्होंने 50 हजार लोगों की स्क्रीनिंग की और एक पैसा नहीं लिया।

लोगों को घर में पहुंचाया खाना

धारावी में 2400 से अधिक हेल्थकेयर वर्कर तैनात हैं जिनमें से 27 प्राइवेट डॉक्टर, 29 नर्स, 68 वार्ड बॉय और 11 को-ऑर्डिनेटर, और दो फार्मासिस्ट हैं। दिघावकर ने बताया, इसके अलावा इस इलाके में खाने के जुगाड़ में परेशान लोगों की पहचान करके उनकी मदद की। हमने लोगों को घर से बाहर नहीं आने दिया बल्कि घर पर ही मदद पहुंचाई। एनजीओ ने अब तक 23 हजार फूड पैकेज डोनेट किए। दिघावकर ने बताया, 'इसके अलावा हाई रिस्क वाले लोगों को क्वांरटीन की सलाह दी गई। हमने लगातार लोगों से संपर्क बनाए रखा और इस वजह से 7,992 लोगों को इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन करने में मदद मिली।

महाराष्ट्र सरकार 'स्थिर और मजबूत', पांच साल का कार्यकाल करेगी पूरा: राकांपा

मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य की महा विकास आघाडी सरकार स्थिर और मजबूत है और यह निश्चित रूप से पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। महाराष्ट्र में इस सरकार को छह महीने पूरे हो गए हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान उनके साथ छह मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस से दो-दो मंत्री शामिल थे और बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। विपक्षी पार्टी भाजपा ने तीनों अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टी द्वारा सरकार गठन करने पर स्थिरता को लेकर सवाल किए थे। भाजपा का कहना था कि यह सरकार कुछ ही समय तक चल पाएगी। इसका हवाला देते हुए राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि सरकार ने छह महीने पूरे कर लिए हैं और यह स्थिर तथा मजबूत है। मलिक ने कहा कि भाजपा ने कहा था कि यह सरकार कम समय तक टिकेगी जबकि यह सरकार निश्चित तौर पर पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मलिक ने आरोप लगाया कि भाजपा इस सरकार की स्थिरता को लेकर बेसिरपैर की बातें करती रहेगी और सरकार इसकी वजह से नहीं गिरने वाली। भाजपा सांसद नारायण राणे ने इस सप्ताह की शुरूआत में महाराष्ट्र के राज्यपाल बी एस कोश्यारी से मुलाकात की थी और कोविड-19 महामारी से निपटने में ठाकरे नीत सरकार की 'विफलता' को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। मलिक ने कहा कि इस सरकार का गठन 'साझा न्यूनतम कार्यक्रम' के तहत हुआ जिसका मसौदा तीनों पार्टियों ने तैयार किया था और तीनो पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, सरकार फिलहाल कोविड-19 के खतरे से लड़ रही है। हम इससे उबरेंगे और सरकार सही तरह से चलाएंगे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

महाराष्ट्र: 'अस्थिरता' की अफवाह के बीच...

बता दें कि प्रदेश सरकार के सुझाव पर राज्यपाल विधानपरिषद की 12 सीटों पर प्रत्याशियों का मनोनयन करते हैं। गठबंधन के नेताओं ने बताया कि इन 12 उम्मीदवारों का नाम राज्यपाल के पास भेजा जाना उन तीन कारकों में से एक है, जिसने प्रदेश बीजेपी को परेशान कर रखा है। बीजेपी इससे लगातार खीझ रही है। ऐसे में बार-बार प्रदेश सरकार की अस्थिरता की अफवाह फैलाने का मतलब है कि बीजेपी अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही है। गौरतलब है कि हाल ही में कई प्रदेशों में गैर-एनडीए सरकारों को गिराने में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है और मुख्य विपक्षी पार्टी की इस दिशा में किए गए प्रयासों को लगातार विफल करने में सफल रही है। सूत्रों की माने तो नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस अपनी ही पार्टी के भीतर फूट के संकट से परेशान हैं। पार्टी के भीतर ब्राह्मण और मराठा ऐंगल को लेकर दोफाड़ हो चुका है।

प्रवासी मजदूरों से नहीं वसूला जाए कोई किराया : सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेन या बस का किराया नहीं लिया जाए। जस्टिस अशोक भूषण, एसके कौल और एमआर शाह की बेंच ने प्रवासी मजदूरों की परेशानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं। इन फंसे हुए मजदूरों से ट्रेन और बस का किराया वसूलने को लेकर उलझन थी। इसे लेकर बेंच ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल किए। साथ ही आदेश भी दिया कि इन मजदूरों से वापस घर जाने के लिए कोई किराया न लिया जाए। बेंच ने मेहता से पूछा कि आखिर सामान्य समय क्या होता है? अगर किसी प्रवासी की पहचान कर ली गई है तो एक हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में उसे शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। वह समय कितना है? ऐसा भी देखने में आया है कि जब एक राज्य ने प्रवासी मजदूरों को भेज दिया और सीमा पर दूसरे राज्य ने कहा कि वह प्रवासियों को अंदर नहीं आने देगा। यह क्या चल रहा है। हमें इस पर नीति चाहिए। बेंच ने प्रवासी मजदूरों से किराये के मसले पर कई सवाल किए। कोर्ट ने कहा, "हमारे देश में हमेशा बिचौलिए रहते हैं। लेकिन, जब किराये के भुगतान का मसला हो तो हम नहीं चाहते कि बिचौलिए हस्पक्षेप करें। इस बात को लेकर साफ नीति होनी चाहिए कि कौन किराये का भुगतान करेगा।" शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि मजदूरों से बस, ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देंगी और उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाएं। जिस राज्य से प्रवासी मजदूर चलेंगे वहां स्टेशन पर उनके भोजन और पानी का इंतजाम किया जाएगा। राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकरण के बाद वे एक प्रारंभिक तिथि पर ट्रेन या बस में चढ़ें, इसकी पूरी जानकारी सभी संबंधित लोगों को बताएगा। बेंच ने कहा कि वह यह बिल्कुल नहीं कह रही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन, जितने प्रवासी मजदूर फंसे हैं, उसे देखते हुए कुछ ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। 26 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर स्वतः संज्ञान लिया था। उसने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कुछ कमियां दिख रही हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रवासी मजदूरों को तुरंत मुफ्त ट्रांसपोर्ट, खाने-पीने और रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा था।

टैली रिपोर्ट्स अब वेब ब्राउजर पर उपलब्ध

मुंबई। भारत का अग्रणी बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रदाता टैली सॉल्यूशन्स टैली एक्सपीरिएंस को वेब ब्राउजर पर लेकर आया है। इस रिलीज के लॉन्च के साथ, टैली का उद्देश्य बिजनेसेस को सहयोग करना है ताकि चाहे व्यापारी कहीं भी हों..कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हों...वो अपने बिजनेस डाटा का आसानी से उपयोग कर पायें। इतना ही नहीं, ये सुरक्षित और निजी तरीके से संभव होगा और उनका डेटा ग्राहक की मशीन पर भी रहेगा। यह रिलीज बिजनेस रिपोर्ट और इन्वॉइस जैसी कारोबारी जानकारी के साथ उद्यमियों को सशक्त बनाता है। यह उनके लिए वेब ब्राउजर्स पर इसे उपलब्ध कराता है और इस तक पहुँच प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रकार के कम्प्यूटर या डिवाइस या टैली इन्स्टॉल करने की निर्भरता को दूर करता है । 4 लाख से ज्यादा कारोबारी मालिक पहले से वेब ब्राउजर पर टैली रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं।

लॉन्च के दौरान टैली सॉल्यूशन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तेजस गोयनका ने कहा, हमारी इस रिलीज का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों के ऑफिस के बाहर रहने के साथ उनके डाटा को देखने और किसी भी समय, किसी भी जगह निर्णय लेने की जरुरत पूरी होने से बिजनेस करने में आसानी के मामले में बड़ा बदलाव आएगा। हम इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि हमारे छोटे बिजनेस ग्राहक उनके बिजनेस डाटा पर अपना नियंत्रण बनाए रखना जारी रखें और इसके ऑफिस के बाहर जाने के संभावित खतरों के बारे में उन्हें चिंता न करनी पड़े। जहाँ एक ओर ग्राहक इसके संरक्षण को लेकर हम पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, वहीं हमें लगता है कि इस तरह का विश्वास हासिल करना और मांग करना दोनों ही अनुचित होगा। साथ ही साथ किसी भी डिवाइस पर कहीं भी उनका डाटा देखने की जरुरत समान रुप से और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे इंजीनीयर्स ने ऐसे ब्रेकथ्रू का निर्माण किया है जो हमारे ग्राहकों के लिए दोनों तरह से फायदेमंद साबित होता है। एक साधारण वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर व्यापारी अपने बिजनेस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही ये डाटा उनके नियंत्रण में ही रहेगा। हमारे ग्राहकों के लिए इंटरनेट का लाभ पहुंचाने वाले और भी ज्यादा शक्तिशाली समाधान लाने की दिशा में यह हमारा पहला प्रमुख प्रॉडक्ट रिलीज है।

→ माननीय सांसद श्री. गोपाल शेट्टी जी ने आक्सा, मालाड बीट पर दिन रात काम कर रहे पोलिस के अधिकारी, कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देते हुवे, उनको प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर श्री विनोद शेलार, विशाल भगत, युनुस खान उपस्थिति थे।

→ माननीय सांसद श्री. गोपाल शेट्टी जी ने मढ़, मालाड मे समुदाय स्वयंपाकघर (community kitchen) द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन बनाने की जा रही व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही इस नेक काम में लगे हुवे लोगो को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर श्री विनोद शेलार, विशाल भगत, युनुस खान उपस्थिति थे।

ट्रम्प की मध्यस्थता की पेशकश पर भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब– पड़ोसी के साथ बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिशें जारी

संवाददाता

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को लद्दाख और सिक्किम में भारत-चीन के बीच जारी विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस पेशकश पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी के साथ मसले का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास जारी हैं। इससे पहले ट्रम्प ने कश्मीर मुद्दे पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की बात कही थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया था। भारत ने कहा था कि यह उसका आंतरिक मसला है। एक दिन पहले चीन ने कहा था कि भारत से साथ सीमा पर स्थित स्थिर और नियंत्रण में है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था- दोनों पक्ष तनाव को कम करने में जुटे हैं, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत और चीन के पास कई कूटनीतिक तंत्र मौजूद हैं। किसी भी हालात का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। श्रीवास्तव ने फिर दोहराया कि भारतीय सेना ने एलएसी (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) का उल्लंघन नहीं किया था। भारत, चीन के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सेना हमारे लीडर्स की सहमति और मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करती है। हम

भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं। लद्दाख में हाल ही में गालवन नाला एरिया के पास चीन और भारत के बीत तनाव बढ़ गया है। एलएसी के पास कई सेक्टरों में चीन करीब 5 हजार जवान तैनात कर चुका है। पड़ोसी के इस कदम के बाद भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में अपने जवान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी महीने दोनों सेनाओं के बीच तीन बार अलग-अलग जगहों पर टकराव हो चुका है। पिछले हफ्ते दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर बातचीत कर मुद्दा सुलझाने की कोशिश भी कर चुके हैं। अगर भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने-सामने हुईं तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद होगा। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, भारत ने पेंगोंग त्सो झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने दो हजार से ढाई हजार सैनिक तैनात किए हैं, साथ ही अस्थाई सुविधाएं भी बढ़ा रहा है। चीन लद्दाख के कई इलाकों पर अपना दावा करता रहा है। भारत-चीन बॉर्डर पर डोकलाम इलाके में दोनों देशों के बीच 2017 में 16 जून से 28 अगस्त के बीच तक टकराव चला था। हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। साल के आखिर में दोनों देशों में सेनाएं वापस बुलाने पर सहमति बनी थी।

चीन की अमेरिका को चेतावनी, ‘नुकसान सबका’

पेइचिंग। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में तनाव जारी है। इसी बीच चीन के प्रधानमंत्री ली किकियांग ने कहा है कि दोनों देशों को अपनी असहमतियों को दूर करना चाहिए और एक-दूसरे के ‘मुख्य हितों’ का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी कि दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पटरी से उतारने के प्रयास से किसी का भी भला नहीं होगा और पूरी दुनिया को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि घातक वायरस के स्रोत पर स्पष्ट विचार होना जरूरी है क्योंकि वह विज्ञान के आधार पर इसका पता लगाने के प्रयासों का समर्थन करते हैं। व्यापार, कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति, हॉन्ग-कॉन्ग में नए सुरक्षा कानून को लेकर चीन की कार्रवाई और विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक सैन्य रवैये को लेकर अमेरिका की चीन के साथ तनातनी चल रही है। चीन के संसद सत्र के अंत में ली ने वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनाव के बारे में सवालों का जवाब दिया। दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि वह दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध तोड़ देंगे।

अमित शाह ने की मुख्यमंत्रियों से बात, क्या लॉकडाउन 5 .0 की चल रही है तैयारी?

नई दिल्ली। इन दिनों भारत में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, जो 31 मई को समाप्त होने वाला है। इसी बीच इसे लेकर भी बातें शुरू हो गई हैं कि लॉकडाउन का पांचवा चरण भी हो सकता है। बातें तो यहां तक हो रही हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि 31 मई को पीएम मोदी मन की बात में लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे नकार दिया। अभी गृह मंत्रालय की तरफ से मन की बात में लॉकडाउन 5.0 की घोषणा की खबरों को

गलत बताए जाने को एक ही दिन बीता है और लॉकडाउन 5.0 को लेकर सुगबुगाहट तेज होती दिख रही है। अब खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन पर देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की है। यानी वह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर के ये जानना चाहते हैं कि राज्य क्या चाहते हैं। साथ ही वह ये भी तय करना चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन 5.0 लागू होगा तो उसके लिए गाइडलाइन्स क्या होनी चाहिए। वैसे भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा। हालांकि, छूट बहुत अधिक हो सकती हैं, जैसी इस समय हैं।

मन की बात में नहीं होगी लॉकडाउन 5.0 की घोषणा

कुछ मीडिया संस्थानों की तरफ से लॉकडाउन के पांचवें दौर को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे थे। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह के दावों में कोई दम नहीं है। गृह मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में साफ कहा था कि लॉकडाउन 5.0 की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ध्यान रहे कि लॉकडाउन की रूपरेखा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) तय करता है।

कोरोना: देश दुनिया का हाल

भारत में अब तक कोरोना वायरस के मामले 1.65 लाख से भी अधिक लोगों में फैल चुके हैं, जबकि करीब 4700 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर ये है कि अब तक 70 हजार से भी अधिक लोग सही हो चुके हैं। अगर दुनिया भर में कोरोना वायरस की बात करें तो करीब 58 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 3.60 लाख लोगों की मौत हो चुकी हैं। हालांकि, अच्छी बात ये है कि करीब 25 लाख लोग सही हो चुके हैं।

सरकार पर भड़के विधायक मसूद अख्तर

...कहा मजदूरों की बदहाल स्थिति का ले संज्ञान, नहीं तो होगा आंदोलन

संवाददाता

सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)। गरीबों और मजदूरों की बदहाल स्थिति पर सरकार ध्यान दें और फौरी तौर पर भूख प्यास से तड़पते बिलखते मजदूरों के खातों में 10000 रुपये और 6 महीने तक प्रतिमाह 7500 रुपये उन्हें दे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को रिहा करते हुए कांग्रेसजनों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लेना सुनिश्चित करें अन्यथा की दृष्टि में कांग्रेस जनों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह बातें सहारनपुर देहात से कांग्रेस विधायक माननीय मसूद अख्तर ने कहीं और आज वह सरकार पर जमकर भड़के, कहा कि आज 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है कि लोग लॉक डॉउन के चलते अपने घरों में कैद हैं, उन्हें रोजी रोटी देना तो बहुत बड़ी बात है,बल्कि उनके बुनियादी हक हकूक पर भी पहरा लगा दिया है। विधायक माननीय मसूद अख्तर ने कहा कि सरकार थाली, ताली बजाने, टॉर्च और दिया जलाने मे मस्त रही, उधर राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी मजदूर भूख प्यास से तड़पता रहा और हजारों हजारों किलोमीटर दूर सड़कों पर पैदल चलकर मरता रहा, मगर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और वह धनाढ्यो और पूंजीपतियों की औलादो को लग्जरी गाड़ियों से उनके घरों तक सुरक्षित भेजने में मस्त रही। विधायक मसूद अख्तर ने कहा कि हम मानते हैं कोरोना एक खतरनाक बीमारी है लेकिन इसकी आड़ में

सरकार ड्रामेबाजी कर जहां जनता को भ्रमित कर रही है, वहीं कोरोना की आड में बड़े पैमाने पर घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। विधायक मसूद अख्तर ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों और कोरोना को लेकर की गई तैयारियों की विफलता तथा मजदूरों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को भाजपा सरकार ने गिरफ्तार कर यह साबित कर दिया है कि वह नहीं चाहती, कि उनके राज में कांग्रेस गरीबों मजदूरों, किसानों और आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। विधायक मसूद अख्तर ने कहा कि जहां देश दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है वहीं मोदी सरकार, सरकारी कंपनियों को बेच कर उन्हें निजी हाथों में देते हुए करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार कर रही है।

10000 रुपये मजदूरों को एकमुश्त और छः महीने तक प्रति माह 7500 रुपये दे सरकार

सरकार प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू की रिहाई और कांग्रेस जनों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लेना करे सुनिश्चित

फर्जी राज्य मंत्री बन कर कर रहे थे पुलिस पर रोब, पुलिस ने पहुंचा दिया हवालात

संवाददाता

सहारनपुर। थाना रामपुर मनिहारान के तेजतर्रार इंस्पेक्टर छोटेलाल के सीयूजी नंबर पर एक कॉल की जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को भाजपा का राज्य मंत्री बता कर रोब गालिब करते हुए फॉरेन चुन्हे टी चौकी आने को और कुछ लोगों को पकड़ कर जेल भेजने को कहा। इंस्पेक्टर छोटे सिंह द्वारा विभाग का नाम पूछे जाने पर उधर से धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया गया जिससे इस्पेक्टर छोटे सिंह के पुलिसिया दिमाग मे शक हुआ और वह फॉरेन की चुनौटी चौकी पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां वह लोग नहीं मिले जिससे इंस्पेक्टर के दिमाग में शक और गहरा इंस्पेक्टर छोटे सिंह द्वारा मामले की तह तक जाने के लिए उक्त नंबर पर कॉल किया गया तो उक्त लोगों ने उन्हें चौकी से 1 किलोमीटर दूर आगे एक खेत पर आने के लिए बोला इंस्पेक्टर छोटे सिंह मौके पर पहुंचे तो वहां पर एक वरना कार जिसका नंबर 11 ८,1000 था। वो खड़ी थी जिसके पास 3 लोग खड़े थे पुलिस को देखकर उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर भागने लगा इंस्पेक्टर छोटे सिंह ने खुद को भाजपा का राज्य मंत्री बताने के बारे में उन लोगों से पूछताछ की तो इस्पेक्टर का शक सही निकला थोड़ी सी पूछताछ करने पर ही उन्होंने सच बता दिया।

हैदराबाद सिंध नेषनल कॉलजिएट, (HSNC) बोर्ड द्वारा संकल्प खादी कवच- खादी मुखावरण, (Face Mask)

मुंबई। आज एच एस एन सी बोर्ड ने अपने सभी संस्थाओं में खादी कवच-खादी मुखावरण के प्रयोग का संकल्प लिया है। एच एस एन सी बोर्ड के अंतर्गत 25 षैक्षणिक संस्थाएँ हैं जिनके द्वारा छात्रों को विज्ञान, कला, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमैंट की विविध षाखाओं द्वारा न केवल षिक्षित किया जाता है अपितु समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए मूल्यपरक षिक्षा एवं कौषल्य के नवीन प्रतिमानों द्वारा उन्हें योग्य भी बनाया जाता है। भारत एवं सम्पूर्ण विष्व इस समय कोरोना वायरस से उत्पन्न अभूतपूर्व महामारी से जूझ रहा है। मुखावरण का प्रयोग इस बिमारी के प्रमुख निवारक उपायों में से एक सषक्त उपाय है। सरकार ने भी प्रत्येक जन के लिए इसका प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणाप्रद भाषण (आत्मनिर्भर भारत) से प्रेरित होकर हमने खादी के प्रयोग का संकल्प लिया है। संरक्षक होने के कारण नवीन भारत के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए हम राष्ट्र-सेवा का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।- श्री किषु मनसुखानी, अध्यक्ष, एच एस एन सी बोर्ड।

हैदराबाद सिंध नेषनल कॉलजिएट, (HSNC) बोर्ड की स्थापना स्वर्गीय विद्यासागर प्राचार्य श्री के एम कुंदनानी जी तथा स्वर्गीय बैरिस्टर श्री एच जी अडवानी जी द्वारा भारत पाक विभाजन के पूर्व सन 1921 में हुई थी। बोर्ड द्वारा आजाद भारत में सर्वप्रथम सन 1949 में आर डी नेषनल महाविद्यालय, बांद्रा तथा 1954 में किषनचंद चेलाराम महाविद्यालय की स्थापना हुई। तब से अब तक बोर्ड अनवरत रूप से सफलता की ऊँचाइयों को छू रहा है। आज बोर्ड के अंतर्गत षिक्षा की विविध धाराओं के 25 षैक्षणिक संस्थानों की स्थापना सफलतापूर्वक हो गई है। जिनमें 45000 से ऊपर छात्र एवं 7000 से ऊपर से षिक्षक एवं षिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं।

खादी कवच-खादी मुखावरण के प्रयोग के संकल्प के अवसर पर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एवं विष्वस्त (ट्रस्टी) डॉ निरंजन हीरानंदानी ने कहा- सभी षैक्षणिक संस्थाओं में एच एस एन सी बोर्ड ने ही सर्वप्रथम यह निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनुमोदित विचारधारा 'स्थानीय चीजों को बढ़ावा दो', 'खादी अपनाओ', 'आत्मनिर्भर भारत' ने हमें विषेष रूप से प्रभावित किया। 'एक्वाक्रॉफ्ट' द्वारा निर्मित 'खादी कवच' जिसका संवर्धन हमारे ही एक भूतपूर्व मेधावी छात्र डॉ सुब्रामन्या कुसनूर ने किया है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की विचारधारा के अनुरूप है, इसकी सहायता (प्रोमोषन) करने में हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। इसकी सहायता से हम इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग भी दे रहे हैं। खादी कवच एक ऐसा मुखावरण है जो खादी कपड़े से बनाया गया है, यह कपड़ा हाथों द्वारा बुना एवं काता गया है। रेष्मी कपड़े की अपेक्षा खादी कपड़ा रोएंदार होता है, आवष्यक नमी को बरकरार रखता है। चूंकि यह साँस लेने में, धोने में, पुनः इस्तेमाल एवं स्वाभाविक तरीके से सड़नषील है अतः इसका इस्तेमाल बहुत सुखद है। 'एक्वाक्रॉफ्ट' ने खादी कवच महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के ग्रामीणों को, मुंबई पुलिस को, अंधेरी (प) के झुग्गी झोपड़ी वालों को एवं सुप्रसिद्ध एन जी ओ 'स्पर्ष गंगा' के माध्यम से भारतीय सेना को भी वितरित किए हैं। एच एस एन सी बोर्ड द्वारा सर्वप्रथम स्थापित आर डी नेषनल महाविद्यालय, बांद्रा की प्रभारी प्राचार्या डॉ नेहा जगतियानी जी का कथन है -खादी कवच के संकल्प का अनुमोदन करना हमारे लिए गर्व की बात है जो हमारे ही नेषनेलिटी के एल्युमनी ऐसोसिएषन के अध्यक्ष एवं 'एक्वाक्रॉफ्ट' के संस्थापक डॉ सुब्रामन्या कुसनूर का उपक्रम है जो स्वयं राष्ट्र निर्माण के कई प्रकल्पों से सन्नद्ध है। कोविड 19 को मात देने के उद्देष्य से बनाया गया यह खादी कवच न केवल षरीर के लिए सुखद है बल्कि यह बहुत सी महिलाओं को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने की अनोखी पहल है। पैकिंग की दृष्टि से खादी कवच के एक पैकेट में तीन नग होंगे और हमने 50000 लोगों तक पहुँचाने का निष्चय किया है अतः हमें 150000 नगों की आवष्यकता है। हम जो मुखावरण दान करेंगे, वो गरीब महिलाओं की आजीविका कमाने में उनकी सहायता भी करेगा, नारी सषक्तिकरण के उपक्रम में यह हमारा विषेष योगदान होगा। यह सम्पूर्ण कार्यभार एच एस एन सी बोर्ड से जुड़े सभी महाविद्यालयों के एन एस एस के छात्रों के द्वारा वहन होगा। यह कवच उन झुग्गी झोपड़ी वालों को एवं ग्रामीणों को दिए जाएंगे जिनको उन्होंने गोद लिया है। इसके साथ साथ वे नुक्कड नाटक, नृत्य एवं सोषल मीडिया द्वारा समाज को जागृत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के खादी के विस्तार एवं आत्मनिर्भरता के संकल्प को जन जन तक पहुँचाएंगे। 'एक्वाक्रॉफ्ट' प्रोजैक्ट प्रा लि के संस्थापक, नेषनेलिटी एल्युमनी ऐसोसिएषन के अध्यक्ष स्वच्छश्री डॉ सुब्रामन्या कुसनूर का कहना है मुझे बहुत खुषी एवं गर्व महसूस हो रहा है कि खादी के प्रति मेरे इस संकल्प को मेरी सर्वप्रथम मातृसंस्था ने सहर्ष स्वीकार एवं अपने नाम के साथ घोषित किया है। खादी कवच का सर्वप्रथम विचार मेरी बेटी चिन्मयी के दिमाग में सृजित हुआ था जिसे मेरी कंपनी ने कार्यरूप दिया। यह संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 08 को पूरा करता है और एच एस एन सी बोर्ड द्वारा किया गया यह संकल्प इस क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। यह कवच देष की सबसे पुरानी खादी सोसायटी द्वारा निर्मित किया गया है जिसकी स्थापना सन 1956 में धारवाड़ में हुई थी।

एच एस एन सी बोर्ड का परिचय

एच एस एन सी बोर्ड के अंतर्गत 25 षैक्षणिक संस्थाएँ हैं और जो षिक्षा की विविध धाराओं विज्ञान, कला, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमैंट एवं विषेषकर व्यायवसायिक प्रषिक्षण द्वारा 45000 छात्रों के सुंदर भविष्य कर रही हैं। यह बोर्ड विष्वस्त एवं अध्यक्ष श्री किष मनसुखानी जी एवं बोर्ड के महान एवं कर्मठ सदस्यों विष्वस्त एवं पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल हरिष जी, विष्वस्त एवं पूर्व अध्यक्ष डॉ निरंजन हीरानंदानी जी, विष्वस्त श्री चेलाराम जी, श्रीमती माया षहानी जी एवं सचिव पद पर प्रतिष्ठित श्री दिनेष पंजवानी जी के सुयोग्य नेतत्व में कार्यरत है। छात्रों के सुंदर भविष्य के निर्माण में सहयोग देने हेतु बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई यात्राएँ एवं सम्बंध बनाए हैं जो छात्रों को आधुनिकीकरण, एकत्रीकरण एवं उनकी सफलता के विस्तार में सहयोगी होंगे।

'एक्वाक्रॉफ्ट' का परिचय

'एक्वाक्रॉफ्ट' प्रोजैक्ट प्रा लि . समाज में पीने के स्वच्छ पानी एवं सभी की स्वच्छता के लिए प्रयत्नषील है। दि इकोनॉमिक्स टाइम्स में 'एक्वाक्रॉफ्ट' को 'चैंपियन ऑफ सस्टेनेबल सोल्युषन' की संज्ञा दी है। यह SDG6 of Global Compact Network India का सहयोगी है। 'एक्वाक्रॉफ्ट' के संस्थापक स्वच्छश्री डॉ सुब्रामन्या कुसनूर द्वारा स्थापित स्वच्छगृह बिल्कुल नवीन सृजना है जिस कारण उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर बहुत यष प्राप्त हुआ है।

80 पर्सेंट कोरोना केस दिल्ली की वजह से, सील रहेगा हरियाणा बॉर्डर: अनिल विज

गुरुग्राम। हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने दिल्ली से लगते अपने जिलों के बॉर्डर को सील रखने का फैसला किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली की सीमा से लगते गुड़गांव और फरीदाबाद में 30-40 केस आ रहे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर को सील रखा जाए। अनिल विज ने राज्य में कोरोना के लिए एक तरह से दिल्ली को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा राज्य के करीब 80 फीसदी कोरोना केस उन

जिलों से हैं जिनकी सीमा दिल्ली से लगती है। विज ने कहा, दिल्ली के जो केसेस हैं और उसके साथ लगते जो हमारे जिले हैं, वे हमारी बहुत बड़ी चिंता हैं। आज ही मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली से लगते जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन पर कोई ढिलाई न बरती जाए। गृह मंत्री विज ने कहा, कोरोना के रोज 30-40 केस गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-30 केस फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे 80 फीसदी जो केस हैं, वे उन जिलों से हैं जिनकी सीमा दिल्ली से लगती है। इसलिए दिल्ली के साथ हम अपने बॉर्डर पूरी तरह सील रखेंगे। बता दें कि गुरुवार को भी हरियाणा में कोरोना वायरस के 123 नए केस मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,504 हो गई है। हालांकि राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 604 है जबकि 881 मरीज पूरी तरह इस बीमारी से उबर चुके हैं। कोरोना से हरियाणा में 19 लोगों की जान गई है।

लॉकडाउन का उल्लघंन करने पर वसूला गया जुर्माना

संवाददाता

टाण्डा (रामपुर)। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे चार पहिया व दो पहिया वाहनों का मुख्य मार्ग नगर पालिका आफिस के पास वाहनों की सधन चेकिंग की गई उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान भी किये गये तथा उनसे जुर्माना भी वसूला गया तथा उनके प्रति नाराजगी भी जताई। कोतवाल माधो सिंह बिष्ट ने मुख्य मार्ग सहित नगरीय अन्य मार्गों का भी भ्रमण किया तथा उल्लंघन करने वालों को डांट डपटकर दोड़ाया गया जिसके चलते कोई भी वयक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन न कर सकें उल्लंघन करने वालों के प्रति सख्त कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये। इस मोके पर कोतवाल माधो सिंह बिष्ट, महिला अंशु एस.आई रामवीर सिंह, सुरेश सिंह, कुलदीप, कुलवंत आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

फेशियल के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां

आजकल चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए महिलाओं का फेशियल करवाना आम बात है। इससे त्वचा की डेड स्किन निकल जाती है और ग्लोइंग बना रहता है। कुछ महिलाएं तो पार्लर जाने की बजाए घर पर भी फेशियल कर लेती है लेकिन फेशियल के बाद आपके द्वारा की गई कुछ गलतियां आपके खूबसूरती को बिगाड़ भी सकती है। फेशियल के बाद आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिनसे चेहरे को कोई नुकसान न हो। आज हम आपको बताएंगे कि फेशियल के बाद किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे चेहरे को कोई नुकसान न हो।

फेशियल के बाद इन बातों का रखें ध्यान

1. फेश वॉश

फेशियल के तुरंत बाद कभी फेशवॉश या साबुन से मुंह न धोएं। इससे त्वचा पर केमिकल रियेक्शन हो सकता है, जो चेहरे को नुकसान पहुंचाता है।

2. धूप में जाना

फेशियल कराने के बाद अपने चेहरे को 5-6 घंटे तक धूप से कवर करके रखें। फेशियल के बाद आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, जिससे त्वचा पर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों का बुरा असर पड़ सकता है।

3. वैक्सिंग

कुछ महिलाएं फेशियल करवाने के बाद फेस वैक्सिंग भी करवाती है लेकिन यह स्किन के लिए खतरनाक हो सकता है। फेशियल के बाद चेहरे पर वैक्सिंग करने के से रेडनेस और रैशेज जैसी समस्या हो सकती है।

4. थ्रेडिंग कराना

फेशियल के बाद त्वचा कोमल हो जाती है। जिससे थ्रेडिंग करवाने पर जलन, खुजली, रैशेज और स्किन कटने जैसी समस्याएँ होने लगती हैं। इसलिए कभी भी फेशियल के बाद थ्रेडिंग न कराएं।

5. मेकअप करना

शादी या किसी पार्टी में जाने के लिए 1-2 दिन पहले ही फेशियल करवाएं। क्योंकि फेशियल के तुरंत बाद मेकअप करने से स्किन को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा इससे स्किन के खुले हुए पोर्स भी बंद हो जाते है।

डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये 5 पौधे

आजकल सेहत के हिसाब से देखा जाए तो हर 5 में तीसरा शख्स डायबिटीज यानी की शुगर का मरीज है। इन मरीजों को अपने खान-पान का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि गलत खान-पान इनकी हालत को और भी खराब कर सकता है। अगर यह आऊट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो शुगर के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन अगर आप अपने आहार में कुछ ऐसे चीजों को शामिल करेंगे जो डायबिटीक प्रॉब्लम को दूर करने में सहायक होती हैं तो आप इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा भी पा सकते है। जैसे नीम के पत्ते खाना, करेला का जूस पीना, जामुन की गुठली का चूर्ण इन लोगों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा कुछ पौधे भी हैं जो इस रोग से मुक्ति दिलाने में काम करते हैं।

चलिए, आज हम आपको ऐसे ही पौधे के बारे में बताते हैं जो घर की सुंदरता के साथ आपको निरोग भी रखते हैं।

1. तुलसी

तुलसी को हमारे हिंदू धर्म में पूजा जाता है और यह आपके सबके आंगन में सजी भी दिखेगी। लेकिन सिर्फ डैकोरेशन ही नहीं बलकि सेहत के लिहाज से भी यह काफी फायदेमंद हैं। सर्दियों में अगर आप तुलसी की चाय पीएंगे तो ठंड से बचे रहेंगे। इसमें तेज एस्ट्रोन वाला स्वाद भरपूर होता है जो तनाव को दूर रखता हैं। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अच्छी हैं क्योंकि इसे ब्लड में शुगर का लेवल सही रहता है।

2. पुदीना

पुदीने का पौधा, हाई और लो दोनों तरह के ब्लडप्रेशर को कंट्रोल में रखता है। पुदीने की चटनी और इसका जूस डायबिटीज लोगों के लिए फायदेमंद हैं इसलिए घर में इसे जरूर लगा कर रखें।

3. धनिया

भोजन में स्वाद व खुशबू बढ़ाने के साथ-साथ हरा धनिया थकान मिटाने में बेहद सहायक है। धनिया में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होने से मधुमेह का रोग खत्म हो जाता है। साथ ही इससे खून में इंसुलिन की मात्रा भी नियंत्रित रहती है। इसके साथ ही यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रोल की मात्रा घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होता है।

4. करी पत्ता

करी पत्ते का इस्तेमाल न सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है बल्कि इससे अनगिनत रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। डायबिटीज के रोगी के लिए करी पत्ता रामबाण का काम करता है। डायबिटीज के रोगियों को 5-6 करी पत्ता रोजाना खाना चाहिए।

5. लहसुन

लहसुन के गुणों के बारे में कौन नहीं जानता। ये अपने आप में ही एक लाजवाब औषधि है। लहसुन एंटिऑक्सीडेंट होने के साथ-साथ एक किस्म का ब्लड प्यूरीफायर है। जो हमारे खून को तो साफ रखता ही है साथ ही हाथ पैरों और जोड़ों के दर्द से भी निजात दिलाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लहसुन के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पौधे हरियाली देने के साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। तो बस इंतजार किस बात का, आप भी इन सेहतमंद पौधों को अपने घर पर उगाकर खुद को बनाइए सुपर हेल्दी।

जापान का स्पेशल फेस मास्क, नियमित इस्तेमाल से दिखेंगी 10 साल छोटी

स्किन ड्राईनेस के कारण दाग-धब्बे और मुंहासे जैसी समस्याएं होने लगती है। इनसे छुटकारा पाने के लिए आप कई ब्यूटी और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते है। इसका बजाए आप घरेलू फेस पैक का यूज करके इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते है। यह नेचुरल फेस पेक आपके चेहरे की डेड स्किन को निकाल कर उसे मॉइश्चराइज करता है, जिससे चेहरा बेदाग और कोमल हो जाता है। किसी पार्टी या फंक्शन में जाने से पहले इसका इस्तेमाल आपके चेहरे को ग्लोइंग बना देगा। सिर्फ 4 चीजों के इस्तेमाल से तैयार होने वाले इस फेस पेक से त्वचा के डेड सेल्स खत्म हो जाएंगे। तो आइए जानते है इस फेस पैक को बनाने ती आसान रेस्पी।

फेस पैक बनाने की रेस्पी

सामग्री:-

एवोकैडो- ¼ (मैश किया हुआ)
1 नींबू का रस
जैतून का तेल- ½ टेबलस्पून
शहद- 1 टेबलस्पून

बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका

1. एक बाउल में सारी सामग्री को डालकर चम्मच की मदद से मैश कर लें।
2. इसे लगाने से पहले चेहरे को साफ करके एक गर्म टावल को चेहरे पर 2-3 मिनट तक रखें। इससे चेहरे के बंद पोर्स खुल जाएंगे।
3. ब्रश या हाथों की मदद से इस पैक को चहरे पर लगाएं।
4. फेस पैक को लगाने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को साफ करें।
5. इसे साफ करने के बाद अपने चेहरे पर सिरम या मॉइश्चराइजर लगाएं।
6. डेड सेल्स को खत्म और स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हफ्ते में 1 बार इस फेस पैक का इस्तेमाल करें।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

माधुरी दीक्षति की आवाज के कायल हुए शाहरुख खान

बॉलिवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने कोरोना लॉकडाउन के बीच सॉन्ग 'कैंडल' के साथ सिंगिंग डेब्यू किया है। उनका यह गाना सुनकर उनके को-स्टार्स उनकी आवाज के दीवाने हो गए। अब इस लिस्ट में शाहरुख खान का नाम जुड़ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की है।कई फिल्मों में माधुरी दीक्षित के को-स्टार रहे शाहरुख खान ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मेरी करियर कलीग और मेरी दोस्त और काफी ज्यादा टैलंटेड सिर्फ एक ही हैं माधुरी दीक्षित उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है और उनसे सीखता रहता हूं। कितनी शानदार आवाज है और वह खुद कितनी अच्छी है। शानदार। शाहरुख खान के ट्वीट करने के बाद उनके फैंस ने माधुरी दीक्षित के साथ उनकी तस्वीरे शेयर करने लगे। इसके अलावा उनकी स्क्रीन पेयरिंग की तारीफें भी कीं। बता दें कि माधुरी दीक्षित के पहले लॉकडाउन के दौरान शाहरुख खान और सलमान खान अपने सॉन्ग रिलीज कर चुके हैं। माधुरी दीक्षित का सॉन्ग 'कैंडल' कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। इसके रिलीज करते हुए माधुरी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, खुश हूं, उत्साहित हूं और थोड़ी नर्वस भी। ये मेरा पहला गाना है उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी अक्षय कुमार की 'लक्ष्मी बम'?

कुछ सप्ताह पहले तक खबरें आ रही थीं कि अक्षय कुमार की फिल्म 'लक्ष्मी बम' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी। वहीं, अब इन खबरों में तथ्य नजर आ रहे हैं। दरअसल, एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के एक्सक्लूसिव प्रीमियर राइट्स एक ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा खरीदे जा चुके हैं और फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। इस लेटेस्ट रिपोर्ट के सोर्स पर विश्वास किया जाए दो शुरूआत में फिल्ममेकर और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बीच कुछ बातों को लेकर मामला अधर में था। अब सब साफ हो चुका है और फिल्म 'लक्ष्मी बम' ऑनलाइन रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 'लक्ष्मी बम' के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की आधिकाारिक घोषणा क्यों नहीं की जा रही है, इस पर बात करते हुए एक सूत्र ने कहा कि निमार्ताओं को प्रॉजेक्ट को तैयार करने के लिए कम से कम एक महीने का समय चाहिए क्योंकि फिल्म के पोस्ट प्रॉडक्शन का काम अभी बचा हुआ था और वह लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। सूत्र ने आगे कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के कम से कम एक महीने बाद तक फिल्म का प्रीमियर नहीं होगा और अभी रिलीज की तारीख भी तय नहीं की गई।

आलिया ने नवाज से की इतनी ऐलिमनी की डिमांड?

बॉलिवुड ऐक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पिछले कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल, नवाज की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उनपर कई संगीन आरोप लगाते हुए तलाक लेने का फैसला लिया है। आलिया का आरोप है कि नवाज अपने बच्चों और पत्नी के लिए वक्त नहीं निकालते और अक्सर उनकी बेइज्जती किया करते थे। आलिया ने तलाक के साथ बच्चों की कस्टडी और ऐलिमनी भी डिमांड की है। सोर्स की मानें, तो नवाज को भेजे गए नोटिस में आलिया ने तीस करोड़ रुपये और यारी रोड में 4 बीएचके फ्लैट मांगा है। आलिया ने परमानेंट ऐलिमनी के रूप में खुद के लिए दस करोड़ रुपये और दोनों बच्चों की सिक्यॉरिटी के लिए दस-दस करोड़ रुपये की फिक्स डिपॉजिट डिमांड की है। साथ ही यारी रोड में 4 बीएचके फ्लैट की मांग की है। हालांकि, जब हमने आलिया और उनके वकील से इस पर बात करनी चाही, तो उन्होंने कॉमेंट करने से इंकार कर दिया। आलिया ने यह कहते हुए फोन काटा, यह मेरा निजी मामला है। मुझे जहां जो दिक्कत हुई थी, उसपर मैंने मीडिया से बात कर ली है। इस पर मुझे कोई बात नहीं करनी है। जो भी बताया जा रहा है, वो गलत है। यह मेरे और नवाज के बीच की बात है। वहीं, नवाजुद्दीन का इस पर कोई ऑफिशल बयान नहीं मिल पाया है।